गये हैं; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे शैक्षिक और सूचनात्मक कार्यक्रमों की बजाये बच्चे चित्रहार, फीचर फिल्म, एनीमेशन फिल्म और धारावाहिकों जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों को देखना अधिक पसंद करते हैं, यदि हां, तो दूरदर्शन सूचनात्मक और शैक्षिक संबंधी अपने लक्ष्य को पूरा करने में कहां तक सफल रहा है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा चित्रहार, फीचर फिल्म, प्रादेशिक फीचर फिल्म, धारावाहिक एनीमेशन फिल्म और खेल जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए कितने-कितने समय का आवंटन किया जाता है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल०भगत) : (क) और (ख) इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आयी हैं। दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान यूनिट तथा बाहरी अभिकरणों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बच्चे फन्तासी, एक्शन और कहानी के तत्व वाले कार्यक्रमों को पसंद करते है। दूरदर्शन का बच्चों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम टेलीकास्ट करने का प्रयास रहा है जो मनोरंजक होने के अलावा शैक्षिक और सूचनापरक होते हैं। तथापि बच्चों को यथोचित बोध कराने के लिए मूलतः शैक्षिक और सूचनापरक कार्यक्रमों को मनोरंजन के साथ जोड़ दिया जाता है।

(ग) मनोरंजक, शैक्षिक और सूचनापरक कार्यक्रमों का सीमांकन करना कठिन है क्योंकि दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट कार्यक्रमों में ये अवयव मिले-जुले होते हैं।

Suspension of the Executive Director of Aonla Project

2793. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Board of Directors of IFFCO has passed a resolution last month suspending the Executive Director of Aonla Project; if so, on what charges; and

(b) whether the Department of Fertilizers has communicated to IFFCO that the resolution would have no effect whatsoever and has asked for reconciliation and review the suspension decision if so, the reasons that the Department has passed the order; what action has been taken in this regard by the IFFCO?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) Yes, Sir. Board of Directors of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) in its meeting held on 7th February, 1989 passed a resolution to suspend the Executive Director (Aonla) for alleged overpayments to 2 transport contractors.

(b) Yes, Sir. Government of India *vide* its order dated 9th February, 1989 declared that the resolution to suspend the Executive Director (Aonla) shall be of no effect whatsoever and further directed that IFFCO shall review and reconsider the matter by following the prescribed procedure in keeping with the principles of natural justice. The above order is being implemented by IFFCO.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

2794. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री अबरार अहमद खान :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं जैसे आटा, चीनी, चावल, दूध, वनस्पति घी, खाद्य तेल, कपड़ा, ईंधन इत्यादि के मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) विशेषत: 1986, 1987 और 1988 के वर्षों में अक्तूबर-नवम्बर के महीनों में इन वस्तुओं का वर्षवार मूल्य क्या रहा है;

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को दीर्घावधि आधार पर स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें फरवरी 1986 तथा फरवरी, 1989 में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक दर्शाये गए हैं **(नीचे रखिये)** ।

(ख) एक विवरण अनबंध में दिया गया है, जिसमें क्रमशः वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 में अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक दिए गए हैं **[देखिये** परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 151] ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा उनकी उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं । सरकारी नीति में मुख्य जोर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कुछ वस्तुओं, जैसे दालों, खाद्य तेलों और चीनी आदि के आयात की अनुमति दी है तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए अन्य उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, अधिक उचित दर की दुकानें खोलना तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की परिवीक्षा करना शामिल है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 से अधिक उचित दर की दुकानें खोली गई हैं और 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार उचित दर की दुकानों की संख्या 3.50 लाख है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षत्र प्रशासनों के समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा समाज-विरोधी तत्वों विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को सख्ती से लागू करें । दूर तक फैले क्षत्रों में कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण मोबाइल वैनों के जरिए भी किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य पर निगरानी रखने के लिए राज्य/जिला उचित दर की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित की गई है । राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई हैं कि वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की नियमित आधार पर परिवीक्षा करें ।

विवरण

फरवरी, 1986 तथा फरवरी 1989 में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक	
	फरवरी, 1986	फरवरी, 1989
चावल	275.5	359.0
गेहूं	244.9	332.2
ज्वार	248.2	369.1
बाजरा	301.1	284.6
चना	583.1	864.2

1	2	3
अरहर	315.6	464.4
मूंग	420.8	728.8
मसूर	504.4	738.0
उड़द	382.3	554.0
आलू	169.7	158.3
प्याज	344.8	437.8
दूध	283.2	392.8
मछली	511.6	627.1
गोश्त	533.5	666.3
चाय	390.2	468.4
लाल मिर्च	192.0	461.4
साफ्ट कोक	606.3	606.3
मिट्टी का तेल	403.5	410.4
साबुन	325.9	466.2
आटा	232.5	353.5
चीनी	303.8	337.8
गुड़	412.6	427.2
वनस्पति	325.1	451.6
मूंगफली का तेल	316.6	384.4
सरसों का तेल	246.2	344.3
नारियल का तेल	238.9	439.6
जिजली का तेल	276.1	363.2
नमक	233.9	254.3
दियासलाई	129.0	129.0
सूती कपड़ा (मिल का)	271.9	291.4
समग्र वस्तुएं	358.9	439.0

रेगिस्तान विकास योजना का असफल होना

2795. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1988 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डैजर्ट डेवलपमेंट प्लान ए फेलियर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने तथ्यों का पता लगाया है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के विफल रहने के क्या-क्या मुख्य कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।